IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उच्च शिक्षा पर नयी शिक्षा नीति २०२० का प्रभाव

डॉ. बबिता देवी

सहायक प्रोफेसर

एशियन कालेज, सरसावा सहारनपुर

यह शोध पत्र "उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रभाव पड़ा पर संदर्शित है। जो मुख्यत नई शिक्षा नीति की व्याख्या करने के साथ–साथ उच्च शिक्षा की गुणवक्ता में क्या प्रभाव पड़ा तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में क्या प्रभाव पड़ा तथा उच्च शिक्षा की परिकल्पना किस प्रकार की गयी है, इस शिक्षा नीति – पर जिन परंपरा, संस्कृति, मनुष्यों और लोकाचार का प्रभाव पड़ा उनकी व्याख्या भी की गयी है। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और परिपक्व होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियो में ज्ञान, कौशल, बुद्धि आत्मविश्वास की वृद्धि करके उनके दृष्टिकोण को विकसित करना है – इस शोधपत्र में शोधकर्ता ने विभिन्न महत्वपूर्ण विन्दुओं पर प्रकाश डाला है उपयुक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर शोधकर्ता ने इस शोधपत्र के – द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा के लिए लाभकारी तत्वो को प्रस्तुत किया है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है

प्रस्तावना – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी गयी, जिसे एक विशेष कमेटी के परामर्श से तैयार किया गया इस शिक्षा नीति के साथ ही देश में शिक्षा पर चर्चा आरंभ हो गयी शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधी जी का तात्पर्य – "बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है ।"

इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि "मनुष्य की अंतनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है ।"

इन्ही सब व्याख्यायो या परिभाषाओं के आधार पर भारत में 1986 की शिक्षा नीति लागू की गयी लेकिन इस शिक्षा नीति में कुछ कमियां रह गयी थी, जो शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण नही कर पायी इन्ही कमियों को पूर्ण करने के लिए नयी शिक्षा नीति बनायी गयी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया तथा परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गयी है। इन उद्देश्यो के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 फीसदी के साथ–साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य –

- अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनायी गयी थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।
- वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के० कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 फीसदी लाने का लक्ष्य रख गया है।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर के 60 हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति की धोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु

- नई शिक्षा नीति में 5३3४ डिजायन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव तैयार किया गया है जो उसे 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
- पाँच वर्ष की फाऊंडेशनल स्टेज – 3 साल का प्री–प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
- तीन वर्ष का प्राइमरी स्टेज
- तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण–ग्लैंड 6, 7, 8
- 4 वर्ष का उच्च (या माध्यमिक) चरण कोड 9, 10, 11, 12

2020 के तहत द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसक द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा तीन स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिशचित किया जायेगा।

भाषायी विविधता का संरक्षण – 2020 में कक्षा–5 तक की शिक्षा में मातृ–भाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

- स्कूली और उच्च शिक्षा में संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओ का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार – इस नीति में भाषा और विज्ञान व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अंतर नहीं होगा। N.C.E.R.T के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए पाठयक्रम की रूप रेखा त्यार की जायेगी।

- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक–निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जायगी।
- छात्रों की प्रगति व मूयांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने लेने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबधित सुधार – शिक्षको की नियुकि में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय–समय किए गए कार्य–प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा छात्रो के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जायेगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकी कृत वी. एड. का होना अनिवार्य किया जायेगा।

उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रावधान – 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानो के सकल नामांकन अनुपात को 26,310 बढ़ाकर 50,010 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानो में 3.5 करोड़ नयी सीटों को जोड़ा जायेगा।

- 2020 तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरो पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगें और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण– पत्र प्रदान किया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम० फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय उच्च्य शिक्षा आयोग – 2020 में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानो लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना दी गयी है, जिसमें अनेक भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होगें भारतीय उच्चा शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पुरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सकल निकाय के रूप में में कार्य करेगा।

उच्च शिक्षा पर 2020 का प्रभाव – राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर (2020 का उच्च शिक्षा पर सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है यह नीति शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाती है। जैसे बहु–विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और विदेशी विश्व विद्यालयों को भारत में स्थापित करने की अनुमति देना।

बहु–विषयक शिक्षा – 2020 उच्च शिक्षा में बहु– विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है जिसमें छात्रों को बहुआयामी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने और उनकी रचनात्मकता को विकसित करने में प्रभावी होगी।

अनुसंधान को प्रोत्साहन – यह नीति अनुसंधान को बढ़ावा देती है, और विश्व–विद्यालयो अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप बनाने पर जोर देती है, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा से खोज को बढ़ावा दे सके तथा शिक्षा व्यवस्था की सुधारा जा सके।

तकनीकी प्रगति – 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षण विधियों और संसाधनों तक पहुँच प्राप्त होगी।

समावेशी शिक्षा – यह नीति समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है जिसका कार्थ है कि शिक्षा सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए चाहे उनकी समाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि लिंग, जाति चर्म या कोई भी क्षेत्र हो।

व्यवसायिक शिक्षा का महत्व – 2020 व्यवसायिक शिक्षा को भी महत्व प्रदान करती है। जिससे छात्रों को नौकरी के बाजार सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त हो सका सके।

उपसंहार – नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यदि इस प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह छात्रों के सम्पूर्ण विकास अनुसन्धान को देने और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची –

1- https://www-education-gov-in/sites/upload---

1. http://en-wikipedia-org/wiki/National Education Policy 2020
2. A Review of the National Education policy of the Government of India& The Need for Data and Dynamism in the 21st century SSRN
3. Vedhathiri Thani Kachalom ¼January 2020½ Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research Journal of Engine ring Education] 33-